www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 146 | जौनपुर शनिवार, 10 जनवरी 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

1962 की हार पर नेहरू की जिम्मेदारी बनती है : शशि थरूर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के एक ताजा बयान ने सियासी रूप से नई हलचल मचा दी है। पिछले कुछ समय से कांग्रेस के आधिकारिक रुख के विपरीत रुख अख्तियार कर रहे शशि थरूर ने कहा है कि वह देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु के प्रशसंक हैं लेकिन उनकी सभी बातों का समर्थन करना संभव नहीं है। केरल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शशि थरूर ने देश की राजनीति में इतिहास को लेकर जारी घमासान के बीच सत्तारुढ़ भाजपा की रणनीति पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु के प्रशंसक हैं, लेकिन अंधभक्त नहीं हैं। शशि थरूर ने कहा कि नेहरु के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, पर यह भी सच है कि उनके हर विचार और हर निर्णय का समर्थन करना न तो जरूरी है और न ही बौद्धिक रूप से यह ईमानदारी होगा। थरूर ने कहा कि नेहरु ने आजाद भारत की लोकतांत्रिक नींव रखी, संस्थानों को आकार दिया और भारत को विश्व पटल पर पहचान दिलाई। इसके बावजूद उनके कुछ निर्णय ऐसे रहे जिन पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 1962 के चीन युद्ध से जुड़े कुछ फैसलों पर नेहरु की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन यह कहना कि देश की आज की हर समस्या की जड़ नेहरु ही हैं, इतिहास के साथ अन्याय है।

एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, 13 जनवरी को अर्जियों पर सुनवाई

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार समेत कई राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए भारत निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर अंतिम सुनवाई 13 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिन में इन याचिकाओं की सुनवाई तय की थी, लेकिन बाद में कहा कि वह मंगलवार (13 जनवरी) को कार्यवाही फिर से शुरू करेगी। चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी मामले में अपनी दलीलें फिर से पेश करने वाले थे। 6 जनवरी को, निर्वाचन आयोग ने पीठ को बताया था कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करने का अधिकार और क्षमता उसके पास है, साथ ही यह सुनिश्चित करना संवैधानिक कर्तव्य है कि किसी भी विदेशी को मतदाता के रूप में पंजीकृत न किया जाए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि कार्यवाही मंगलवार को फिर से शुरू की जाएगी। मामले में चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी को अपने तर्क आगे बढ़ाने थे। 6 जनवरी को चुनाव आयोग ने पीठ को बताया था ।

राजनाथ सिंह ने किया अशोक लेलैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट का उद्घाटन

लखनऊ, (संवाददाता)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राजधानी के सरोजनी नगर क्षेत्र में अशोक लेलैंड के अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों का है, इसी दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आने वाले वर्षों में पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन प्रमुख होंगे। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से ईवी को बढ़ावा देना आवश्यक है और सरकार भविष्य की तकनीकों पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए नियमों को सरल किया गया है और उद्योगों को ऑनलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से सहूलियत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अशोक लेलैंड का यह संयंत्र केवल एक कंपनी की सफलता नहीं, बल्कि उद्योग जगत के सरकार की नीतियों पर बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। डबल इंजन की सरकार के तहत उत्तर प्रदेश में कानून–व्यवस्था, सड़कों और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण निवेश का माहौल सुदृढ़ हुआ है। राजनाथ सिंह ने बताया कि संयंत्र का निर्माण 24 महीनों में प्रस्तावित था, लेकिन रिकॉर्ड 18 महीनों में इसे पूरा किया गया। यहां परिचालन शुरू होने के बाद हर महीने लगभग 2,500 इलेक्ट्रिक वाहन तैयार किए जाएंगे। इससे स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और अगले पांच वर्षों में हजारों करोड़ रुपये के निवेश तथा लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए 'फॉर्च्यून ग्लोबल 500 एवं फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनी निवेश प्रोत्साहन नीति–2023' लेकर आई है। साथ ही 'उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस एवं डिफेंस यूनिट और रोजगार प्रोत्साहन नीति' के माध्यम से राज्य को रक्षा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनाया जा रहा है। राजनाथ ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक, यानी 2047 में, उत्तर प्रदेश रोजगार, उद्योग, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में देश का नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि यही विकसित भारत का सपना और संकल्प है। राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए बताया कि वर्ष 2014 में भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन मात्र 46 हजार करोड़ रुपये था, जो आज रिकॉर्ड बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। इसी तरह, रक्षा निर्यात जो पहले 1,000 करोड़ रुपये से भी कम था, अब रिकॉर्ड 24,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के प्रयासों के चलते भारत का रक्षा क्षेत्र तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।

पीएम मोदी का गुजरात दौरा– सोमनाथ में ओंकार जाप, भव्य ड्रोन हाउस में भी होंगे शामिल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 जनवरी 2026 तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री 10 जनवरी की शाम को सोमनाथ पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान के अनुसार, वे रात करीब 8 बजे ओंकार मंत्र का जाप करेंगे और उसके बाद सोमनाथ मंदिर में ड्रोन शो देखेंगे। बयान के अनुसार, 11 जनवरी को सुबह करीब 9:45 बजे, प्रधानमंत्री मोदी शौर्य यात्रा में भाग लेंगे, जो सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले अनगिनत योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित एक औपचारिक जुलूस है। इसके बाद, सुबह करीब 10:15 बजे, प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। सुबह करीब 11 बजे, प्रधानमंत्री सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। दिन में आगे, प्रधानमंत्री कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए आयोजित वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजकोट जाएंगे। दोपहर लगभग 1:30 बजे, वे सम्मेलन में आयोजित व्यापार मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे।

वित्त मंत्री ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ की आने वाले बजट पर चर्चा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के छात्रों के साथ आने वाले बजट पर चर्चा की।इसे लेकर निर्मला सीतारमण के ऑफिस की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई एक पोस्ट में कहा गया कि वित्त मंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के छात्रों के साथ आगामी केंद्रीय बजट 2026–27 के संबंध में नई दिल्ली में एक पूर्व–बजट वार्ता आयोजित की, जिसका नेतृत्व इसके निदेशक प्रोफेसर राम सिंह ने किया।इस चर्चा के दौरान, छात्रों ने स्किलिंग, ग्रीन एनर्जी, ग्रामीण विकास, नई अर्थव्यवस्था आदि विषयों पर केंद्रीय बजट में विचार करने के लिए कई सुझाव प्रस्तुत किए। नवंबर 2025 में डीएसई में डायमंड जुबली विदाई भाषण देते हुए वित्त मंत्री ने डीएसई के छात्रों को केंद्रीय बजट के लिए अपने सुझाव साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया था। पोस्ट में अंत में कहा गया कि सतत शैक्षणिक सहभागिता के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रथा हर साल जारी रहनी चाहिए और अर्थशास्त्र का अध्ययन करने वाले युवा छात्रों से विचार प्राप्त किए जाने चाहिए ताकि देश के बजट को हर साल दिशा देने में मदद मिल सके।

अब यूपी अपनी क्षमताओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश : सीएम योगी

लखनऊ, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व रक्षामंत्री ने लखनऊ में अशोक लीलैंड के इलेक्ट्रिक वाहन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने फैक्ट्री का उद्घाटन करने के बाद ई–बस में सफर भी किया। फैक्ट्री का निर्माण सरोजनी नगर इलाके में करीब 70 एकड़ में किया गया है। यहां पर ई–बस, ई–ट्रेवलर और ई–लोडिंग वाहन बनाए जाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह हमारे लिए महत्वपूर्ण अवसर है। इसके लिए मैं हिंदुजा परिवार को बधाई देता हूं। यह निवेश बताता है कि यूपी में बीते आठ वर्षों में क्या परिवर्तन हुए हैं। प्रदेश के हर जिले में निवेश हो रहा है। जो कि बताता है कि अब यूपी अनलिमिटेड पोटेंशियल का ही प्रदेश नहीं बल्कि पोटेंशियल को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन चुका है। आज यूपी न सिर्फ देश के बल्कि दुनिया के निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बन चुका है। यही कारण है कि यूपी में निवेश के लिए 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। प्रदेश में बीते आठ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो काम हुआ है यही कारण है कि आज देश के 55 फीसदी एक्सप्रेस वे यूपी में हैं। प्रदेश में रैपिड रेल बनाई जा रही है। आज प्रदेश में 18 हजार स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इस मौके पर भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि यह सिर्फ प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आत्मनिर्भर भारत और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में बड़ा कदम है। यह भारत के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। इस मौके पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि योगी जी जिस तरह से यूपी को चला रहे हैं। उससे सहज ही प्रदेश की रेटिंग एक्सीलेंट कही जा सकती है। अशोक लीलैंड कंपनी की इस ईवी फैक्टरी का उद्घाटन प्रदेश के औद्योगीकरण की दिशा में मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ से सांसद हूं पर अगर मैं लखनऊ का न भी होता तो भी यह शहर मुझे उतना ही प्रिय होता जितना कि आज है ।

अमित शाह ने लॉन्च किया देश का पहला राष्ट्रीय आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, आतंरिक सुरक्षा मजबूत होगी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भारत के पहले राष्ट्रीय आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया। यह कदम देश की काउंटर–IED और आतंरिक सुरक्षा संरचना को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एनआईडीएमएस को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा विकसित किया गया है। यह एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो आईईडी से संबंधित डेटा के संग्रह, समेकन और वितरण को व्यवस्थित करने में मदद करेगा। वर्चुअल उद्घाटन के दौरान अमित शाह ने कहा कि इंटर–एजेंसी समन्वय भी अब और बेहतर होगा। यह सही समय और सही जगह पर सही जानकारी पहुंचाने का एक बहुत प्रभावी तरीका होगा। एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई थी और तब से इसने दुनिया भर में हुए आतंकवादी हमलों का विश्लेषण किया है और किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार किया है। आतंकवाद रोधी गतिविधियां, हाइजैकिंग विरोधी ऑपरेशन, बम निष्कासन की उन्नत प्रणाली और अब सभी एजेंसियों के साथ डेटा साझा करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना ये सभी एनएसजी के महत्वपूर्ण कार्य हैं। एनएसजी के डायरेक्टर जनरल ब्रिघु श्रीनिवासन ने बताया कि पिछले 11 महीनों में अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर इस सिस्टम को तैयार किया है। उन्होंने इसे भारत का अनूठा प्लेटफॉर्म बताया। एनआईडीएमएस के माध्यम से राज्य पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और अन्य केंद्रीय एजेंसियां डेटा को एक्सेस, विश्लेषण और साझा कर सकेंगी। इससे आतंकवाद और विद्रोही हमलों की रोकथाम में तेजी आएगी और जांच प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सकेगा। इस प्लेटफॉर्म से फोरेंसिक विश्लेषण, ट्रेनिंग मॉड्यूल और ऑपरेशन योजना में सुधार होगा। आईईडी अक्सर आतंकवादी और विद्रोही समूहों द्वारा सुरक्षा बल और आम जनता को निशाना बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। एनआईडीएमएस के जरिए टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर देश की तैयारी बढ़ाई जा सकेगी और किसी भी घटना के समय तेजी से प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी।

लोगों की जिंदगी की तबाह लगाए सिलसिलेवार आरोप : राहुल गांधी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमलावर हैं। एक दिन पहले जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ट्रंप के टैरिफ को लेकर कड़ा निशाना साधा था। वहीं अब उन्होंने एक लंबे–चौड़े एक्स पोस्ट के जरिए भाजपा शासित राज्यों पर सिलसिलेवार हमला किया है। कांग्रेस सांसद ने शुक्रवार को अपने बयान में आरोप लगाते हुए कहा कि देशभर में भ्रष्ट जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों ने जनता की जिंदगी तबाह कर दी है। राहुल गांधी ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के साथ सत्ता का दुरुपयोग और अहंकार का जहर भाजपा की राजनीति में ऊपर से नीचे तक फैल चुका है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा, इनके सिस्टम में गरीब, असहाय, मजदूर और मध्यमवर्ग की जिंदगी सिर्फ आंकड़ा है और विकास के नाम पर वसूली–तंत्र चल रहा है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया – लेकिन सवाल आज भी वही है। सत्ता का संरक्षण भाजपा के किस वीआईपी को बचा रहा है? कानून सबके लिए बराबर कब होगा? उन्होंने यूपी और इंदौर का मुद्दा उठाते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश के उन्नाव कांड में भी पूरा देश देख चुका है कि सत्ता के गुरूर में अपराधियों को कैसे बचाया गया और पीड़िता को न्याय के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ी। इंदौर में जहरीला पानी पीकर मौतें हों या गुजरात–हरियाणा–दिल्ली तक काले पानी और दूषित सप्लाई की शिकायतें हर तरफ बीमारियों का डर है।

ममता बनर्जी का आचरण शर्मनाक और असंवैधानिक, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार–तार किया : रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कोलकाता में आई–पैक कार्यालय पर ईडी की रेड के बाद सियासी बवाल जारी है। इसी बीच शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने प्रेसवार्ता कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को बंगाल में जो हुआ, वह आजाद भारत में पहले कभी नहीं हुआ। सीएम ममता बनर्जी का पूरा काम न सिर्फ अनैतिक, गैर–जिम्मेदार और असंवैधानिक है, बल्कि उन्होंने पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शर्मसार कर दिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ष्आजाद भारत के बंगाल में जो हुआ, वो आज तक नहीं हुआ। एक निजी प्रॉपर्टी में, जहां ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग पर कार्रवाई चल रही थी, वहां एक मौजूदा मुख्यमंत्री चली जाएं और ईडी के लोगों को धमकाएं और पेपर छीनकर चली जाएं। कोयले की स्मगलिंग और हवाला ट्रांजैक्शन को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत कई जगह रेड हुई। प्रतीक जैन की कंसल्टेंसी फर्म को लेकर शिकायत आई कि यहां से करोड़ों रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है। उन्होंने कहा कि ये हम नहीं कह रहे हैं, ईडी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है, जो उनकी वेबसाइट पर मौजूद है। ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल का हाल बेहाल हो गया है। आपको मालूम है कि बंगाल कोयले की स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट है, जिसमें सत्ताधारी दल के लोग भी शामिल हैं। रविशंकर ने कहा कि मैं आपको बता दूं कि ये रेड न तो ममता बनर्जी के घर पर थी, न उनके दफ्तर में, न ही टीएमसी के दफ्तर में और न ही टीएमसी के किसी नेता या मंत्री के घर पर थी। ये रेड एक निजी कंसल्टेंसी फर्म पर थी, जिसके यहां करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी।

सपनों की नगरी मुंबई में जनसंख्या का बदलता गणित

मुंबई, (एजेंसी)। मुंबई की पहचान और जनसांख्यिकी आज एक बड़े राजनीतिक चौराहे पर खड़ी है। चुनावी आहट के साथ ही यह बहस छिड़ गई है कि क्या सत्ता की खींचतान में शहर का मूल स्वरूप बदल रहा है? विपक्षी गठबंधन, महाविकास आघाड़ीपर यह आरोप मढ़े जा रहे हैं कि उनके नीतिगत फैसले एक विशेष समुदाय के वर्चस्व को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे मुंबई की सांस्कृतिक विरासत और पहचान संकट में पड़ सकती है। आर्थिक राजधानी का यह बदलता चेहरा अब भविष्य के लिए एक गंभीर प्रश्नचिह्न बन गया है। आगामी 2026 बीएमसी चुनाव से ठीक पहले, मुंबई के जनसांख्यिकीय ढांचे में हो रहे बदलाव और वोट–बैंक की राजनीति ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। शहर का युवा वर्ग अब यह सवाल उठा रहा है कि क्या मुंबई का भविष्य शहरी नियोजन से नहीं, बल्कि राजनीतिक समीकरणों से तय हो रहा है? इस सियासी संग्राम के केंद्र में महाविकास आघाड़ीपर लग रहे गंभीर आरोप हैं। आलोचकों का दावा है कि एमवीए शासन के दौरान लिए गए कई नीतिगत फैसले निष्पक्ष शासन के बजाय एक खास जनसांख्यिकीय पैटर्न को बढ़ावा देने के लिए थे। विपक्षी नेताओं के अनुसार, झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास, कल्याणकारी योजनाओं के वितरण और नागरिक नियुक्तियों को इस तरह डिजाइन किया गया जिससे खास वार्डों में राजनीतिक प्रभाव और बजट पर दीर्घकालिक नियंत्रण हासिल किया जा सके। मुंबई की गलियों में अब अवैध बस्तियों के विस्तार और उनके पीछे छिपी चुनावी मंशा को लेकर चिंताएं गहरी हो रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सत्ता हथियाने के लिए किए जा रहे ये राजनीतिक प्रयोग मुंबई की मूल पहचान और इसके संसाधनों पर भारी पड़ सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का तर्क है कि मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में दो–तरफा चुनावी रणनीति काम कर रही है। एक तरीका कथित तौर पर हिंदू मतदाताओं को जाति, भाषा और क्षेत्रीय आधार पर बांटता है। दूसरा तरीका आश्वासनों, प्रतीकात्मक पहुंच और लक्षित लाभों के माध्यम से मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की कोशिश करता है। आलोचकों का मानना घ्ह्है कि यह रणनीति लगातार चुनावों में कई शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है। आरक्षण की मांग और क्षेत्रीय पहचान के मुद्दों को अक्सर सामाजिक न्याय के कारणों के रूप में पेश किया जाता है। हालांकि, विरोधियों का तर्क है कि इन बहसों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि हिंदू समुदाय बंटे रहें।

संपादकीय

भारतीय उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ गया

ये मामला भारत में मोनोपॉली, ड्यूओपॉली और कार्टेल्स बनने की बढ़ती गई शिकायतों की पुष्टि है। इसी का परिणाम है कि उत्पादन संबंधी इनपुट लागत ऊंची बनी रही है, जिससे निवेश और बाजार के विस्तार के लिए प्रतिकूल स्थितियां बनी हैं। कॉम्पीटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि बड़ी स्टील उत्पादक कंपनियों टाटा, जिंदल स्टील और सेल ने कई अन्य छोटी कंपनियों के साथ मिल कर कार्टेल (गुट) बनाया और देश में इस्पात की कीमत मिल–जुल कर तय की। 2015 से 2023 के बीच की कई अवधियों में ऐसा किया गया। यानी इन कंपनियों ने आपस में अपेक्षित प्रतिस्पर्धा नहीं की। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से ही उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद उचित मूल्य पर मिल सकते हैं। जबकि उत्पादक कंपनियां मिलीभगत कर लें, तो गुणवत्ता पर समझौता करते हुए या मनमानी कीमत वसूलते हुए वे अपना मुनाफा बढ़ाती हैं। इसीलिए ऐसी प्रवृत्ति रोकने का कानून है। सीसीआई की जांच इस नतीजे पर पहुंची कि स्टील उत्पादक कंपनियों ने संबंधित कानून उल्लंघन किया। सीसीआई के पास मामला बिल्डरों की अर्जी से पहुंचा, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि नौ स्टील कंपनियों ने मिलीभगत से बाजार में स्टील की उपलब्धता घटाई, ताकि वे महंगी दर पर अपने उत्पाद बेच सकें। सीसीआई ने इन कंपनियों के 56 अधिकारियों को दोषी ठहराया है, जिन पर भारी जुर्माना लगाए जाने की संभावना है। स्पष्टतरू ये घटना भारतीय अर्थव्यवस्था में मोनोपॉली (एकाधिकार), ड्यूओपॉली (द्वि–अधिकार) और कार्टेल्स बनने की बढ़ती गई शिकायतों की पुष्टि है। इसी का परिणाम है कि उत्पादन संबंधी इनपुट लागत ऊंची बनी रही है, जिससे निवेश और बाजार के विस्तार के लिए प्रतिकूल स्थितियां बनी हैं। हैरतअंगेज यह है कि ऐसी कंपनियों की सहायता के लिए सरकार भी सहर्ष आगे रही है। बीते हफ्ते ही केंद्र ने डंपिंग रोकने के नाम पर आयातित स्टील पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाया। उसके बाद भारतीय स्टील कंपनियों ने अपने उत्पाद की कीमत में 2 से 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी। यानी भारतीय उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ गया है। मुद्दा यह है कि जो उद्योग घराने अर्थव्यवस्था की बुनियादी जरूरतों पर अपने मुनाफे को इस तरह तरजीह दे रहे हों, क्या सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए? देश के अंदर वे प्रतिस्पर्धा को रोक रहे हैं, तो उन्हें आयातित उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर करने में क्या बुराई है?

क्रिकेट मैदान के बाहर रन-आउट

अरविन्द

मुस्तफिजुर वाले फैसले से, जिसे लेकर वे काफी दुखी, हैरान और परेशान थे, क्रिकेट खेल और प्रशासन की परेशानियां बढ़ गई हैं और आने वाले दिनों में यह विवाद और उलझ सकता है। एक तो बांग्लादेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आगामी टी–20 विश्वकप के भारत में होने वाले मुकाबलों में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया। उन्होंने आयोजक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल को यह सूचना दी और उसकी बात मान ली गई। शाहरुख खान का चरित्र अब किसी के प्रमाणपत्र की मांग नहीं करता और जिस तरह से उन्होंने अपनी कोलकाता नाइटराइडर टीम के लिए खरीदे गए बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रिलीज कर दिया है। उससे प्रमाणपत्र मांगने वाले मुट्ठीभर लोगों का मुंह बंद हो चुका है इनमें चुनाव हारकर खाली बैठे संगीत सोम, एक धर्म गुरु, एक मौलाना, कांग्रेस में जाने समेत कई चक्कर लगाने के बाद शिवसेना में लौटे एक नेता शामिल हैं। संगीत सोम ने तो यह फैसला करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने मुस्तफिजुर के हवाई अड्डे से बाहर न निकालने देने की घोषणा की थी। अब उन्होंने यह घोषणा किस बल से की या किसके इशारे से, यह बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह क्रिकेट बोर्ड और शाहरुख खान का फैसला हुआ उससे साफ है कि उनको देश की सर्वोच्च सत्ता से जरूरी निर्देश और संदेश मिले थे। यह फैसला अटपटा है और इसका रिश्ता पिछले दिनों सम्पन्न चौंपियंस ट्राफी और एशियाई टी–20 मुकाबले में पाकिस्तान के साथ खेलने लेकिन पाकिस्तानी अध्यक्ष से ट्राफी लेने या पाकिस्तानी कप्तान से हाथ न मिलाने के फैसले से जुड़ता दिखता है। जाहिर तौर पर वह सब भी क्रिकेट के हमारे कर्ताधर्ता लोगों के निर्देश पर ही किया गया था। यह अलग बात है कि मीडिया का एक वर्ग और भाजपा के कई लोग उसके लिए भी वाह वाह कर रहे थे।लगता है कि मुस्तफिजुर वाले फैसले से, जिसे लेकर वे काफी दुखी, हैरान और परेशान थे, क्रिकेट खेल और प्रशासन की परेशानियां बढ़ गई हैं और आने वाले दिनों में यह विवाद और उलझ सकता है। एक तो बांग्लादेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आगामी टी–20 विश्वकप के भारत में होने वाले मुकाबलों में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया। उन्होंने आयोजक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल को यह सूचना दी और उसकी बात मान ली गई। तर्क वही खिलाड़ियों की सुरक्षा का है। मुस्तफिजूर को बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के मद्देनजर रोकने की मांग थी तो अब बात खिलाड़ियों की सुरक्षा पर आ गई। याद करें तीन दशक पहले की जब एशियाई क्रिकेट शीर्ष पर था और भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश मिल कर प्रतियोगिताएं आयोजित करते थे। यह विश्व कप या पिछला एशिया कप भी इसी तरह साझा तौर पर आयोजित हो रहा है। पिछली बार तो भारत– पाक मुकाबले दुबई में करा लिए गए और व्यावसायिक रूप से खास नुकसान न हुआ। खिलाड़ियों को भी ज्यादा भाग–दौड़ नहीं करनी पड़ी थी।लेकिन इस बार प्रारम्भिक दौर में ही बांग्लादेश को भारत में चार मुकाबले खेलने हैं, तीन कोलकाता में और एक मुंबई में। पाकिस्तान और भारत को एक दूसरे के यहां नहीं ही खेलना है। साफ है कि सारा वजन श्रीलंका पर आएगा। और अगर बांग्लादेश अंतिम आठ वाले लीग में और फिर सेमीफाइनल तथा फाइनल तक पहुंच गया तो आयोजकों को मैदान तय करने और खिलाड़ियों को वक्त से पहुंचाने तथा आराम का इंतजाम करने में पसीने छूट जाएंगे। इन सबके बीच खेल का क्या होगा यह तो सोचना भी मुश्किल है। और कई लोग तो 2031 तक एशिया के देशों द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के मुकाबलों के भविष्य को लेकर भी परेशान हैं जिन्हें भारत, नेपाल और बांग्लादेश को आयोजित करना है। अगर इसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर एक दूसरे के यहां न जाने के फैसले पर अड़े रहे तो क्या स्थिति होगी, यह सोच पाना भी कठिन है। 2031 में भारत और बांग्लादेश को एक दिवसीय क्रिकेट के विश्व कप का साझा आयोजन करना है।ये चीजें जब तक आयोजकों और भारतीय क्रिकेट के प्रमुख लोगों के दिमाग में साफ हों तथा उसका नफा–नुकसान समझ आये तब तक बांग्लादेश सरकार ने एक और फैसला लेकर सबकी और क्रिकेट की हालत और मुश्किल कर दी। उसने मुस्तफिजुर वाले फैसले की प्रतिक्रिया में आईपीएल के टीवी प्रसारण पर रोक की घोषणा कर दी। आज दुनिया के क्रिकेट प्रेमी दर्शकों में भारत नंबर एक है और उनसे अप्रत्यक्ष कमाई ही वह कारण है जिसमें हम क्रिकेटरों को (और उनको ही क्यों दूसरे खेलों को भी मदद करते हैं) ऐसा भुगतान करने लगे हैं।

'तत्वमसि' में है प्रचारकों की जिंदगी का बयान

संजय

देश में हुए सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तनों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति सामान्यजन की जिज्ञासा बढ़ा दी है। इस बीच अपनी यात्रा के 100 साल संघ ने पूरे कर लिए हैं। इसलिए संघ की संपर्क गतिविधियां भी सामान्य दिनों से ज्यादा हैं। ऐसे समय में संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्रीधर पराड़कर का उपन्यास 'तत्वमसि' बड़ी सरलता से आरएसएस के बारे में बताता है। यह उपन्यास एक आत्मकथात्मक उपन्यास भी कहा जा रहा है, जिसके केंद्र में खुद लेखक और उसके अनुभव हैं। बावजूद इसके एक प्रचारक की जिंदगी के बहाने संघ को समझाने में यह उपन्यास पूरी तरह सफल है। कहानियों से चीजों को बताना आसान होता है, विचार कई बार भ्रमित भी करते हैं और उन्हें समझना सबके बस की बात नहीं। उसे वही ग्रहण कर सकता है जिसकी उस विचार विशेष में रुचि हो। शायद इसीलिए पूज्य सरसंघचालक डा. मोहन भागवत इस बात को रेखांकित करते रहे हैं कि "संघ को संघ के भीतर आकर ही समझा जा सकता है।" अपनी स्थापना के समय से ही संघ कुछ शक्तियों के निशाने पर रहा है। खासकर आजाद भारत में उसे इसके दंश कई बार भोगने पड़े। श्रीधर पराड़कर का यह उपन्यास उनके अर्जित अनुभवों का बयान भी है। इसलिए इस कृति की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। सही मायनों में यह भोगा हुआ सत्य है, जिसकी अनुभूति इसे पढ़ते समय सहज ही होती है। हम जानते हैं कि श्रीधर पराड़कर, संघ प्रेरित अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे हैं और लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। एक लेखक,चिंतक,विचारक और संगठनकर्ता के नाते वे राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिलब्ध हैं। ऐसे सरोकारी व्यक्ति का लेखन निश्चित ही बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर आता है। किसी भी उपन्यास या कहानी की सबसे बड़ी सफलता है उसकी रोचकता। कहानी को सुनने–पढ़ने का मन होना। कथारस में बहते चले जाना। विचार और संगठन जैसी बोझिल समझी जाने वाली कथा को भी पराड़करजी ने जिस अंदाज में व्यक्त किया है उसने पुस्तक की पठनीयता बनाए रखी है। यह किताब न सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार तत्व, प्रचारकों की जीवन शैली, संघ के समावेशी चरित्र का बयान करती है बल्कि किस तरह वह समाज परिवर्तन को व्यक्ति परिवर्तन के माध्यम से संभव कर रहा है इसे भी बताती है। उपन्यास के मुख्य पात्र परितोष बाबू संघ के प्रचारक हैं। प्रचारक परंपरा के बारे में समाज में न्यूनतम जानकारियां हैं। इस किताब में 'प्रचारक परंपरा' जो सामान्य वस्त्रों में रहकर भी 'साधु परंपरा' का पालन करती है का विषद वर्णन है। समाज जीवन में काम करते हुए आने वाली कठिनाइयों से लेकर,समाज के प्रश्नों का उत्तर भी प्रचारक खोजते हैं। भाषा की रवानी और कथा शैली ऐसी कि संगठन शास्त्र जैसे विषयों को किस्सागोई के साथ कहने में लेखक सफल रहे हैं। पत्रकार अनंत विजय ने किताब के फ्लैप पर ठीक ही लिखा है कि–"मेरे जानते हिंदी के किसी लेखक ने किसी संगठन को केंद्र में रखकर इस तरह का उपन्यास नहीं लिखा है। यह अभिनव प्रयोग है, जिसके मोहजाल में पाठक का पड़ना तय है। पुस्तक के आरंभ में ही अपनी रेलयात्रा के माध्यम से परितोष बाबू न सिर्फ अपना स्वभाव,विचार रख देते हैं बल्कि समाज को लेकर अपनी सोच को भी प्रकट करते हैं। पहले दृश्य से बांध लेना इसे ही कहते हैं। यह उपन्यास एक कर्मनिष्ठ प्रचारक की जिंदगी से गुजरते हुए समाज के अनेक प्रश्नों के उत्तर भी देता चलता है। इसमें जो पात्र हैं वे बहुत सुनियोजित तरीके से कथा के उद्देश्य को पूरा करने में सहयोग करते हैं। विभिन्न

पंथों और विचारों से जुड़े पात्रों का संवाद भी परितोष बाबू से होता है। यहां यह भी प्रकट होता है कि वे व्यक्ति से व्यक्ति का संवाद पसंद करते हैं। मुस्लिम युवा अफरोज से संवाद का अवसर आता है तो वे अपने सहयोगी से कहते हैं,–" उन्हें बुलाना नहीं हम उनसे मिलने उनके घर जाएंगें।" इससे पता चलता है कि संघ की कार्यपद्धति क्या है। जहां वह व्यक्ति से नहीं बल्कि परिवार से जुड़ता है ताकि उनसे सच्चा जुड़ाव हो सके। उनके सुख–दुख अपने हो जाएं। यह उपन्यास इस अर्थ में विशिष्ठ है कि यह अपने समय और उसके सवालों से जूझता है। उसके ठोस और वाजिब हल खोजने की कोशिशें भी करता है। संवाद के माध्यम से यह उपन्यास जो कहता है उसे बहुत बड़े वक्तव्यों से नहीं समझाया जा सकता। प्रो. संजय कपूर, विदेशी मूल की युवती नोरा, महेश बाबू, अफरोज,सदानंद, अनिता और स्नेहल जैसे पात्रों के बहाने जो ताना–बाना बुना गया है वह अप्रतिम है। सदानंद,अमित और स्नेहल से हुए संवाद में परितोष बाबू जिस तरह संघ से जुड़े सवालों के उत्तर देते हैं,वैसे ही वे समाज और परिवार के मुद्दों पर राय रखते हैं। वे एक ऐसे बुजुर्ग की तरह पेश आते हैं जिस पर सबकी आस्था है। भारतीय परिवारों में बुजुर्गों की भूमिका क्या होनी चाहिए, क्या है इसे भी परितोष बाबू की छवि में देखा जा सकता है। परितोष बाबू जैसे लोग जिन्होंने अपना परिवार नहीं बनाया, उसकी मनोभूमि कैसे तैयार होती है। कैसे वे सब कुछ त्यागकर अपने समाज और देश की बेहतरी के स्वयं को आत्मार्पित कर देते हैं। यह सीखने वाली बात है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बहुत से बने हुए भ्रमों, दुष्प्रचारों को यह उपन्यास एक जवाब है। भगवा ध्वज को गुरू मानना और सरसंघचालक परंपरा जैसे विषय भी सहज संवाद से सरल लगने लगते हैं। समकालीन कथासाहित्य में प्रायः एक ही तरह की कहानियां और उपन्यास पढ़कर जिस तरह के मनोविकार और अवसाद उपजते हैं, उसके बीच में यह उपन्यास एक ठंडी हवा के झोंके की तरह है। यह पाठकों को एक संगठन और उसके प्रचारक की कथा तो सुनाता ही है, नए भारत के निर्माण में जुटे राष्ट्रप्रेमियों से भी परिचित कराता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) भारतीय समाज के पुनर्गठन की वह प्रयोगशाला है, जो विचार, सेवा और अनुशासन के आधार पर एक सांस्कृतिक राष्ट्र का निर्माण कर रही है। 1925 में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार की अनोखी भारतीय दृष्टि से उपजा यह संगठन आज अपनी शताब्दी मना रहा है। यह केवल संगठन विस्तार की नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक–सांस्कृतिक पुनरुत्थान की एक अनवरत यात्रा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सही निगाहों से देखना और उसका उचित मूल्यांकन किया जाना अभी शेष है, यह उपन्यास उस दिशा में एक सार्थक प्रयास है।

अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के झूठे दावों पर कब चुप्पी तोड़ेगा भारत

नीरज

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसा दावा किया है जो तथ्यों से कोसों दूर है। हम आपको बता दें कि एक राजनीतिक कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा कि भारत ने अमेरिका से 68 अपाचे हमला हेलीकॉप्टर खरीदे हैं और इनकी डिलीवरी में देरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनसे मिलने आए थे और बोले थे कि "सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं"। ट्रंप यहीं नहीं रुके। उन्होंने यह भी जोड़ा कि रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर टैरिफ लगाए गए और इससे मोदी खुश नहीं थे। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत ने कुल 28 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। इनमें 22 हेलीकॉप्टर वायुसेना के लिए पहले चरण में लिए गए थे और 6 हेलीकॉप्टर बाद में सेना के लिए खरीदे गये। न तो 68 हेलीकॉप्टर खरीदे गए और न ही ऐसा कोई रिकॉर्ड है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी डिलीवरी देरी को लेकर ट्रंप के पास गए हों। डिलीवरी में जो सीमित देरी हुई वह तकनीकी और आपूर्ति कारणों से थी और उसे दोनों देशों के रक्षा तंत्र ने आपसी समन्वय से सुलझाया। ट्रंप का यह बयान न केवल गलत है बल्कि जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया प्रतीत होता है। दिलचस्प बात यह है कि इस बयान पर नई दिल्ली ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। सरकार की ओर से न तो खंडन आया और न ही स्पष्टीकरण। कूटनीतिक हलकों में इसे लेकर असहजता जरूर महसूस की गई लेकिन सार्वजनिक तौर पर चुप्पी बनाए रखी गई। देखा जाये तो यह कोई पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर झूठे या अतिरंजित दावे किए हों। साथ ही यह समझना जरूरी है कि अपाचे हेलीकॉप्टर कोई साधारण रक्षा सौदा नहीं हैं। यह भारत की सामरिक क्षमता का एक अहम हिस्सा हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर आधुनिक युद्ध में जमीन पर सेना को सीधी और घातक हवाई सहायता देने के लिए जाने जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में और तेज रफ्तार सैन्य अभियानों में इनकी भूमिका निर्णायक होती है। चीन और पाकिस्तान जैसी चुनौतियों के बीच भारत के लिए यह प्लेटफॉर्म सामरिक संतुलन बनाए रखने का एक मजबूत औजार है। ऐसे में इन हेलीकॉप्टरों की संख्या को गलत तरीके से पेश करना केवल आंकड़ों की गलती नहीं है। यह भारत की सैन्य तैयारी और रणनीतिक सोच को गलत रोशनी में दिखाने का प्रयास है। जब कोई अमेरिकी नेता यह कहता है कि भारत ने 68 हेलीकॉप्टर खरीदे, तो यह संदेश जाता है कि भारत पूरी तरह अमेरिकी हथियारों पर निर्भर है और अमेरिका के दबाव में फैसले करता है। यह धारणा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के बिल्कुल खिलाफ है। देखा जाये तो ट्रंप की राजनीति का यह तरीका पुराना है। वह हर अंतरराष्ट्रीय सौदे को अपने व्यक्तिगत पराक्रम की तरह पेश करते हैं। उनके लिए भारत कोई साझेदार नहीं बल्कि एक मंच है, जिस पर खड़े होकर वह अपने घरेलू समर्थकों को यह दिखा सकें कि उन्होंने अमेरिका के लिए कितने अरब डॉलर के सौदे कराए। अब सवाल उठता है कि नई दिल्ली चुप क्यों है। क्या यह कूटनीतिक समझदारी है या राजनीतिक मजबूरी? हालांकि कूटनीतिज्ञों का कहना है कि हर बयान पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं और ट्रंप जैसे नेता को नजरअंदाज करना ही बेहतर है। देखा जाये तो भारत और अमेरिका के रिश्ते सिर्फ किसी एक नेता पर निर्भर नहीं हैं। रक्षा सहयोग, तकनीकी साझेदारी, हिंद प्रशांत रणनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन जैसे मुद्दे इन रिश्तों की बुनियाद हैं। लेकिन रिश्तों की मजबूती का मतलब यह नहीं कि झूठ को बिना चुनौती के स्वीकार कर लिया जाए। खासकर तब, जब वह झूठ भारत की गरिमा और संप्रभु निर्णय क्षमता पर सवाल खड़ा करता हो। मोदी सरकार ने अब तक खुद को मजबूत और आत्मविश्वासी नेतृत्व के रूप में पेश किया है। ऐसे में यह उम्मीद की जाती है कि जब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को गलत तरीके से पेश किया जाए, तो एक स्पष्ट और तथ्यात्मक जवाब आए। यह जवाब आक्रामक होना जरूरी नहीं, लेकिन सटीक जरूर होना चाहिए। ट्रंप का बयान एक चेतावनी भी है। यह दिखाता है कि वैश्विक राजनीति में सच से ज्यादा कहानी बिकती है। अगर भारत अपनी कहानी खुद नहीं बताएगा, तो दूसरे लोग उसे अपने हिसाब से गढ़ते रहेंगे। बहरहाल, चुप्पी कभी कभी रणनीति हो सकती है, लेकिन बार बार की चुप्पी अंततः सवाल बन जाती है।

गांधीजी की विरासत से वैश्विक भारत तक

अरुण

भारत पिछले कई वर्षों से विश्व में सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजा गया रेमिटेंस न केवल विदेशी मुद्रा भंडार को सुदृढ़ करता है, बल्कि अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्टार्टअप सहित छोटे व्यवसायों को भी आधार देता है। जून 2025 तक भारतीय बैंकों में एनआरआई जमा राशियां लगभग 3.6 बिलियन डॉलर रहीं, जबकि वित्त वर्ष 2024–25 में रेमिटेंस बढ़कर 135.46 बिलियन डॉलर पहुंच गया।इतिहास की कुछ तिथियां केवल अतीत की स्मृति नहीं, भविष्य की दिशा भी तय करती हैं। 9 जनवरी ऐसी ही एक तिथि है, जब 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली। राजनीतिक निराशा के दौर में उन्होंने देश का भ्रमण कर भारत की आत्मा को समझा और व्यापक जन–आंदोलन की नींव रखी। इसी ऐतिहासिक वापसी की स्मृति में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता हैकृजो गांधीजी की विरासत और विदेशों में बसे भारतीयों के योगदान दोनों का सम्मान करता है।भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय वाला देश है। 1990 में जहां प्रवासी भारतीयों की संख्या लगभग 66 लाख थी, आज विश्व भर में लगभग 3.5 करोड़ भारतीय रहते हैं, जिनमें करीब 1.6 करोड़ अप्रवासी भारतीय और लगभग 1.95 करोड़ विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीय मूल के लोग शामिल हैं। विभिन्न अनुमानों के अनुसार, अमेरिका में 55 लाख, संयुक्त अरब अमीरात में 36 लाख और मलेशिया में 28 लाख भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं। इसके अलावा अन्य देशों में भी बड़ी संख्या में भारतीय बसे हुए हैं। खाड़ी देशों में कुल प्रवासी भारतीयों का लगभग आधा हिस्सा निवास करता है। यूरोप और खाड़ी देशों में भारतीय कुशल एवं अर्ध–कुशल पेशेवरों की बढ़ती मांग के चलते श्रमिकों की अंतरराष्ट्रीय आवाजाही अब केवल आर्थिक विषय नहीं रह गई है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक संवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। आज भारत कई देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों में कौशल–आधारित श्रम सहयोग, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित आव्रजन को केंद्रीय विषय के रूप में आगे बढ़ा रहा है।भारत पिछले कई वर्षों से विश्व में सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजा गया रेमिटेंस न केवल विदेशी मुद्रा भंडार को सुदृढ़ करता है, बल्कि अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्टार्टअप सहित छोटे व्यवसायों को भी आधार देता है। जून 2025 तक भारतीय बैंकों में एनआरआई जमा राशियां लगभग 3.6 बिलियन डॉलर रहीं, जबकि वित्त वर्ष 2024–25 में रेमिटेंस बढ़कर 135.46 बिलियन डॉलर पहुंच गयाकृपिछले वर्ष से करीब 14 प्रतिशत अधिक, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच प्रवासी भारतीयों के भरोसे और निरंतर योगदान को दर्शाता है।प्रवासी भारतीयों ने विज्ञान और शिक्षा में वैश्विक नवाचार को बढ़ावा दियाकृ जैसे कल्पना चावला, सत्य नडेला और सुंदर पिचाईय राजनीति में ऋषि सुनक, अनिरुद्ध जगन्नाथ, महिला प्रवासियों ने व्यापार और सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दियाकृजैसे इंदिरा नूयी, और मीरा नायरय वहीं रविशंकर, जुबिन मेहता जैसे कलाकारों ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के माध्यम से भारत की वैश्विक छवि को सशक्त किया। संकट की घड़ियों में प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भी स्पष्ट होती हैकृकोविड–19 के दौरान रेमिटेंस जीवनरेखा बना रहा, जबकि 2018 की केरल बाढ़ में खाड़ी देशों से व्यापक आर्थिक और राहत सहायता पहुंची। राष्ट्रीय स्वाभिमान के संकट में भी प्रवासी भारतीय भारत के साथ मजबूती से खड़े रहे। इसका सशक्त उदाहरण मई 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण हैं, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने अपनी परमाणु क्षमता का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के प्रशासन ने ग्लेन संशोधन के तहत अनेक आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इस चुनौतीपूर्ण समय में वाजपेयी के आह्वान पर एनआरआई समुदाय ने रेमिटेंस बढ़ाया इससे विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिरता मिली और प्रतिबंध काफी हद तक निष्प्रभावी हुए। यह सहयोग आर्थिक ही नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता और आत्मसम्मान के प्रति प्रवासी भारतीयों की गहरी प्रतिबद्धता का प्रमाण था।भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने प्रवासी भारतीयों को विकास–यात्रा से जोड़ने के लिए कई पहलें की हैं। ओसीआई कार्ड ने वीजा–मुक्त यात्रा, संपत्ति स्वामित्व और व्यापारिक भागीदारी को आसान बनाया है, जबकि एनआरईधएनआरओ खाते और एफसीएनआर जमाएं सुरक्षित निवेश व कर रियायतें देती हैं। डिजिटल भारत के तहत यूपीआई के अंतरराष्ट्रीय विस्तार से विदेशी मोबाइल नंबरों के माध्यम से भी भारत में भुगतान और लेन–देन संभव हुआ है। इसके अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के नियमों को सरल बनाकर निवेश, व्यापार और रेमिटेंस से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान किया गया है। कर नियमों के अनुसार एनआरआई की वही आय भारत में कर योग्य मानी जाती है जो भारत में स्थित संपत्ति, व्यापार, सेवाओं या आय–स्रोत से उत्पन्न होकृजैसे संपत्ति के हस्तांतरण से पूंजीगत लाभ, भारत में दी गई सेवाओं का वेतन, भारतीय कंपनियों से लाभांश, ब्याज तथा भारत से जुड़ी रॉयल्टी या तकनीकी सेवा शुल्क। साथ ही, दोहरी कराधान से बचाव समझौतों के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करती है कि एक ही आय पर भारत और विदेशकृदोनों जगह कर न देना पड़े, जिससे प्रवासी भारतीयों को कर–राहत मिलती है। संकट की घड़ी में हेल्पलाइन, पासपोर्ट सेवाएं और कांसुलर सहायता यह सुनिश्चित करती हैं कि प्रवासी विदेश में भी देश का संरक्षण और सहयोग पा सकें। प्रवासी भारतीय चाहते हैं कि निवेश प्रक्रियाएं सरल और पारदर्शी हों, दोहरी नागरिकता पर व्यापक संवाद हो, और संपत्ति, कर व उत्तराधिकार कानून स्पष्ट हों, ताकि वे दीर्घकालीन योजना बना सकें। साथ ही, वे अपने बच्चों को शिक्षा, संस्कृति और भाषा के माध्यम से भारत से जुड़े रहने के पर्याप्त अवसर चाहते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों और पहचान के साथ दृढ़ता से जुड़ी रहें। ट्रम्प प्रशासन द्वारा लागू उच्च टैरिफ और पेशेवर भारतीयों से जुड़े वीजा निर्णय वहां बसे भारतीयों के लिए चिंता का विषय हैं, जिससे रोजगार और आय पर दबाव पड़ा और भारत से आयातित वस्तुएं महंगी हुई हैंय इस संदर्भ में वे भारत सरकार से प्रभावी कूटनीतिक हस्तक्षेप की अपेक्षा रखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य का संकल्प है। कभी जिन्हें ब्रेन ड्रेन का प्रतीक माना गया, वही प्रवासी आज ब्रेन गेन और इनकम गेन के रूप में ज्ञान, तकनीक, निवेश और वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से भारत की सामर्थ्य बन चुके हैं। उनकी उद्यमिता और नवाचार आर्थिक शक्ति को सुदृढ़ करते हैं, जबकि संस्कृति, भाषा और मूल्यों का प्रसार भारत की सॉफ्ट पावर को वैश्विक स्तर पर मजबूत करता है। भौगोलिक दूरी के बावजूद उनकी जड़ें भारत में हैं, और उनकी बौद्धिक व आर्थिक भागीदारी भारत को उभरती शक्ति से आगे बढ़ाकर वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाती है। प्रवासी भारतीय दिवस हमें याद दिलाता है कि जहां भी भारतीय हैं, वहां भारत जीवित हैकृआर्थिक सामर्थ्य, सांस्कृतिक चेतना और मानवीय मूल्यों के साथ।

शिक्षा मंत्रालय ने मांगी शिक्षकों की जानकारी, संघों ने इस निर्णय का किया स्वागत

लखनऊ, (संवाददाता)। टीईटी मामले में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के एक सितंबर 2025 के निर्णय के संदर्भ में राज्यों से इस निर्णय से प्रभावित होने वाले शिक्षकों की संख्या व विवरण मांगा गया है। साथ ही निर्णय का शिक्षकों की सेवा शर्तों, वेतन व वित्तीय स्थिति पर प्रभाव के बारे में जानकारी मांगी है। ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया निर्णय शिक्षकों के संघर्ष की जीत है। संगठन के बैनर तले शिक्षकों ने कई कार्यक्रम चलाए थे। शिक्षामंत्री से मिलकर शिक्षकों की पीड़ा को बताया गया, साथ ही दिल्ली में देशभर के शिक्षकों ने धरना–प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए साल में देश भर के लाखों शिक्षक को केंद्र सरकार के माध्यम से टीईटी अनिवार्यता से राहत मिलेगी। बृहस्पतिवार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (एबीआरएसएम) के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से दिल्ली में मिलकर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) मामले में शिक्षकों को राहत देने की मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल ने सभी सेवारत शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्य किए जाने पर गहरी चिंता जताई। कहा कि यदि इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया, तो इससे देश भर के लगभग 12 लाख शिक्षकों की सेवा–सुरक्षा, वरिष्ठता, पदोन्नति व आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। एबीआरएसएम के अध्यक्ष प्रो. नारायण लाल गुप्ता, महासचिव प्रो. गीता भट्ट ने कहा कि एनसीटीई की अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कक्षा एक से 8वीं तक के शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यताएं अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगी। इससे पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट रहेगी। शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से इस मामले में अधिकारियों को समुचित व आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। प्रतिनिधिमंडल में संगठन मंत्री महेंद्र कपूर, जी लक्ष्मण, महेंद्र कुमार, शिवानंद सिंदनकेरा, प्रो. महेंद्र श्रीमाली, हनुमंत राव, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ यूपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रो. संजय मेधावी, प्रदेश महामंत्री जोगेन्द्र पाल सिंह, आदि शामिल थे।

कौशल विकास विभाग की ओर से लखनऊ में होना था आयोजित

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश कौशल विकास विभाग की ओर से प्रस्तावित रोजगार मेले को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अगली तिथि निर्धारित कर युवाओं को जानकारी दी जाएगी। राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुक्रवार यानी 9 जनवरी को रोजगार मेला आयोजित होना था। इसी के साथ ही अन्य

मंडलों में भी अलग–अलग तिथियां निर्धारित की गई थी। हालांकि विभाग ने भौतिक तैयारी न होने की वजह से इसे आगामी तिथि तक पोस्टपोंड किया है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रोजगार मेले में प्रदेश की 50 से अधिक कंपनियां शामिल होनी थी इसमें 2500 से अधिक बच्चों को रोजगार से जोड़ने की पहल की गई है। विभाग की ओर से अंतिम तैयारियां होने के बाद युवाओं को जानकारी दी जाएगी।

संक्षिप्त खबरें

प्रदर्शनी में 150 कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित

लखनऊ, (संवाददाता)। कैसरबाग स्थित राज्य ललित कला अकादमी में तीन दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी "सृजन" का आगाज बृहस्पतिवार को हुआ। प्रदर्शनी में शहर के करीब 150 उभरते एवं प्रतिष्ठित कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि सहायक नॉर्कोटिक्स आयुक्त, केंद्रीय नॉर्कोटिक्स ब्यूरो एसके सिंह ने किया। उन्होंने युवा चित्रकारों एवं कलाकारों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रदर्शित चित्रों में कलाकारों की मेहनत, लगन और आंतरिक भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति दिखाई देती है। निरंतर परिश्रम से ये युवा कलाकार भविष्य में देश का नाम रोशन करेंगे। प्रदर्शनी 10 जनवरी तक शाम 4 बजे से दर्शकों के अवलोकन के लिए खुली रहेगी।

अखंड महारुद्राभिषेक का हुआ समापन

लखनऊ, (संवाददाता)। गोमतीनगर स्थित श्री हनुमान गढ़ी मंदिर में बृहस्पतिवार को सात दिवसीय श्री अखंड महारुद्राभिषेक एवं शिव शक्ति महायज्ञ का समापन हुआ। यज्ञाचार्य पं. कृष्णदेव पांडेय ने शंखनाद, वैदिक मंत्रोच्चार से पूजा अर्चना कराई। कार्यक्रम की शुरुआत पंचांग पीठ पूजन और अग्नि स्थापना के साथ हुई। इसके बाद महारुद्राभिषेक और शिव शक्ति महायज्ञ हुआ। इसमें मुख्य आचार्य प्रपन्नम, सर्वेश दीक्षित, वगेश मिश्रा, आदेश दीक्षित, आचार्य राघव शर्मा, अभिषेक तिवारी, पंडित चोटी वाले, सागर मिश्रा, कृपा राम पांडेय, ऋषि दुबे आदि शामिल रहे।

समय रहते रिश्तों को संभाल लेने की सीख दे गया नाटक ब्लैक होल

लखनऊ, (संवाददाता)। बिम्ब सांस्कृतिक समिति की ओर से कैसरबाग स्थित राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में बृहस्पतिवार को निर्देशक महर्षि कपूर के नाटक ब्लैक होल का मंचन हुआ। संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली की रंगमंडल योजना और भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से पेश किए गए इस नाटक में पद, पैसा और प्रतिष्ठा की अंधी दौड़ में डूबती मानवीय नैतिकता का सशक्त रूपक बनकर उभरा। लेखक राम किशोर नाग के इस नाटक ने आधुनिक परिवार की टूटती संरचना को गहरे बिंबों में उकेरा। कथा एक उच्चपदस्थ अधिकारी कुरु और उसकी पत्नी आशी के इर्द–गिर्द घूमती है, जिनकी महत्वाकांक्षाएं उन्हें अपने बच्चों से भावनात्मक रूप से दूर कर देती हैं। परिणामस्वरूप संतानें भटकाव, अकेलेपन और मानसिक संघर्ष के अंधेरे में फंस जाती हैं। नाटक का सबसे प्रभावशाली क्षण तब आता है, जब नौकर भोले काका का बेबाक संवाद जीवन मूल्यों की उपेक्षा पर करारा प्रश्न खड़ा करता है। यह संवाद दर्शकों को सोचने पर विवश कर देता है कि सफलता की दौड़ में हम किस हद तक अपने ही अस्तित्व से दूर चले गए हैं। मंच पर गुरुदत्त पांडेय, रितु श्रीवास्तव, मुस्कान सोनी, आकाश सैनी, महर्षि कपूर और विवेक रंजन सिंह के सशक्त अभिनय ने कथा को जीवंत बना दिया। ब्लैक होल एक चेतावनी है कि यदि समय रहते रिश्तों और मूल्यों को नहीं संभाला गया, तो चमक के पीछे केवल शून्य शेष रह जाएगा।

रायबरेली एम्स में बनेगा कैंसर संस्थान व ट्रॉमा सेंटर, मार्च से पहले शुरू हो सकता है निर्माण

लखनऊ, (संवाददाता)। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में जल्द ही मरीजों को और बेहतर स्वास्थ सुविधाएं मिलनी शुरू होंगी। कैंसर संस्थान, हाईटेक ट्रॉमा सेंटर व नर्सिंग कॉलेज को स्वास्थ्य मंत्रालय से स्वीकृति मिल गई है। उम्मीद है कि मार्च से पहले भवन निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। एम्स में ओपीडी की शुरुआत 13 अगस्त 2019 से हुई थी। धीरे–धीरे एम्स का विस्तार शुरू हुआ। कुछ माह बाद मरीजों को भर्ती भी किया जाने लगा। जुलाई 2023 से इमरजेंसी सेवा भी शुरू की गई। इमरजेंसी में 24 घंटे सर्जरी की भी सुविधा मिल रही है। वर्तमान में 40 से अधिक विभागों के माध्यम से मरीजों को विशेषज्ञ सेवाएं मिल रही हैं। ट्रॉमा सेंटर व कैंसर संस्थान के प्रस्तावों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने पास कर दिया है। नर्सिंग कॉलेज भी स्वास्थ्य मंत्रालय से पास हो चुका है। प्रस्तावों पर वित्त विभाग में काम चल रहा है। यहां से स्वीकृति मिलने के साथ ही भवनों के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। वित्त विभाग को प्रस्तावों में कुछ कमियां मिली हैं। एम्स के स्तर से इन कमियों को दूर कराया जा रहा है। इनके दूर होते ही काम शुरू हो जाएगा। ट्रॉमा सेंटर विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही अत्याधुनिक जांच उपकरणों से लैस होगा। प्रस्तावित ट्रॉमा सेंटर में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनेंगे। यहां एक ही छत के नीचे सभी बीमारियों के गंभीर मरीजों के इलाज के साथ ही सर्जरी की सुविधा होगी। मल्टीस्पेश्यलिटी केस हैंडल किए जा सकेंगे। ऑर्गन रिट्रीवल केस भी आसानी से किए जा सकेंगे। सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सहित अन्य सभी प्रकार की जांच मशीनें ट्रॉमा सेंटर में उपलब्ध होंगी। एम्स में 100 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भवन तैयार हो चुका है। इसके शुरू होने से एम्स में क्रिटिकल केयर ब्लॉक आईसीयू, आईसोलेशन बार्ड, हाई डिपेंसिव यूनिट (एचडीयू) वेंटिलेटर के साथ हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। करीब 44.50 करोड़ की लागत से यह ब्लॉक किया गया है। एम्स के अपर चिकित्सा अधीक्षक प्रो. नीरज श्रीवास्तव का कहना है कि दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर जैसी सुविधाएं यहां भी मिल सकेंगी। हाईटेक ट्रॉमा सेंटर, कैंसर संस्थान व नर्सिंग कॉलेज के प्रस्ताव 66 स्वास्थ्य मंत्रालय से स्वीकृत होने के बाद वित्त विभाग भेजे गए हैं। जल्द ही प्रक्रिया पूरी होते ही भवनों के निर्माण का काम शुरू होगा।

जगद्गुरु मध्वाचार्य द्वार के रूप में विकसित किया जाएगा राम मंदिर का गेट नंबर तीन

लखनऊ, (संवाददाता)। राम मंदिर के गेट नंबर तीन को जगद्गुरु मध्वाचार्य द्वार के रूप में विकसित किया जाएगा। इस द्वार का नए सिरे से निर्माण अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। इस कारण द्वार को तीन माह के लिए बंद रखा जाएगा। इस दौरान इस द्वार से राम मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं को अब गेट नंबर 11 जगद्गुरु शंकराचार्य द्वार से वीआईपी श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा। बृहस्पतिवार को मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव व एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे, कार्यदायी संस्था यूपी राजकीय निर्माण निगम के इंजीनियरों सहित अन्य अधिकारियों ने निर्माण कार्य की योजना को अंतिम रूप दिया। तय हुआ है कि तीन से चार महीने के लिए गेट नंबर तीन को बंद कर दिया जाए, ताकि निर्माण कार्य सुचारु रूप से चलता रहे। गेट का निर्माण वंशी पहाड़पुर के लाल पत्थरों से किया जाएगा। इस पर टाइटेनियम से बने दरवाजे लगाए जाएंगे। द्वार की डिजाइन लगभग फाइनल कर ली गई है। द्वार की ऊंचाई करीब 11 मीटर होगी। अब पहले की तरह शंकराचार्य द्वार से वीआईपी व वीवीआईपी श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश देने की योजना है। अब तक निर्माण के चलते इस द्वार को बंद रखा गया था। निर्माण प्रभारी गोपाल राव ने बताया कि राम मंदिर में चार द्वार बनने हैं, जिनमें से तीन द्वार का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मंदिर परिसर के उत्तरी द्वार को भी खोल दिया गया है। इस द्वार से सुरक्षा एजेंसियों के अफसरों, निर्माण में लगे इंजीनियरों व श्रमिकों को प्रवेश दिया जाता है।

संक्षिप्त खबरें

आयुष्मान योजना में क्लेम निस्तारण में बड़ा सुधार

लखनऊ, (संवाददाता)।योगी सरकार गरीबों और जरूरतमंदों को बेहतर, सुलभ और समयबद्ध स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जहां लाभार्थी परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है, वहीं योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित कर पूरी व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि बीते एक वर्ष में आयुष्मान योजना के अंतर्गत क्लेम निस्तारण की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के सूचीबद्ध अस्पतालों से प्राप्त होने वाले क्लेम के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण के लिए लगातार सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी 2025 में क्लेम की पेंडेंसी जहां 10 लाख 75 हजार तक पहुंच गई थी, वहीं दिसंबर 2025 तक इसे घटाकर मात्र 3 लाख कर दिया गया है, जिसे भी शीघ्र ही निस्तारित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर माह औसतन 2 लाख से अधिक क्लेम प्राप्त होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले क्लेम का समयबद्ध निस्तारण एक बड़ी चुनौती है, इसके बावजूद यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पुराने लंबित मामलों के साथ–साथ नए क्लेम का भी नियमित और व्यवस्थित ढंग से निस्तारण हो, ताकि अस्पताल बिना किसी हीलाहवाली के आयुष्मान कार्डधारकों का इलाज जारी रखें।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर क्लेम निस्तारण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मेडिकल ऑडिट व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है। साचीज की एसीईओ पूजा यादव ने बताया कि मेडिकल ऑडिटरों की संख्या 40 से बढ़ाकर 130 कर दी गई है, जिससे क्लेम की जांच प्रक्रिया में तेजी आई है।

गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी ने सुनीं समस्याएं

लखनऊ, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार सुबह गोरखपुर प्रवास के दौरान गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सरकार का संकल्प है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ यह सुनिश्चित किया जाए कि बिना किसी भेदभाव के सभी को न्याय मिले, हर पात्र व्यक्ति को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, जरूरतमंदों के इलाज में कोई बाधा न आए और भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले भू–माफिया व दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनीं। वह स्वयं कुर्सियों पर बैठे लोगों तक पहुंचे और उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुना। मुख्यमंत्री ने सभी प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए ।

विद्यालयों में समाचार पत्र पठन और भाषाई-तार्किक कौशल संवर्धन को लेकर दिशा निर्देश

लखनऊ, (संवाददाता)। अध्यक्ष, बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड और प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, डॉ. एम.के. शन्मुगा सुन्दरम ने उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु समाचार पत्र पठन और भाषाई एवं तार्किक कौशल संवर्धन को बढ़ावा देने के निर्देश जारी किए हैं।डॉ. शन्मुगा सुन्दरम ने बताया कि अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को केवल पाठ्यक्रम की शिक्षा तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें सामान्य ज्ञान, भाषाई पकड़ और आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए भी प्रेरित किया जाए। इसके लिए समाचार पत्रों का नियमित पठन आवश्यक है। इसी उद्देश्य से बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने 23 दिसंबर 2025 को विस्तृत निर्देश निर्गत किए हैं।निर्देशों के तहत प्रत्येक अटल आवासीय विद्यालय में पुस्तकालय में प्रतिष्ठित हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्र नियमित रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। छात्रों को समाचार पत्र पढ़कर विज्ञान, अर्थव्यवस्था, खेल, नवीन विकास और अन्य महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा, प्रार्थना सभा के उपरांत कक्षा में पठन–पाठन प्रारंभ करने से पहले 10 मिनट का समय समाचार पठन के लिए निर्धारित किया जाएगा। प्रतिदिन पांच नए या कठिन शब्दों के अर्थ भी बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएंगे।कक्षा नौ से बारह तक के छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार संपादकीय लेखों पर आधारित मौलिक लेखन या समूह चर्चा आयोजित की जाएगी। कनिष्ठ वर्ग के छात्रों के लिए विज्ञान, पर्यावरण और खेल जैसे विषयों पर न्यूज क्लिपिंग स्क्रैपबुक तैयार करवाने का निर्देश भी दिया गया है।मानसिक विकास और प्रतियोगिताओं के अंतर्गत छात्रों की तार्किक क्षमता बढ़ाने हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित सुडोकू, शब्द पहेली और ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा, छात्रों को विद्यालय समाचार पत्र या त्रैमासिक पत्रिका तैयार करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिसमें उनकी टीम द्वारा विद्यालय की गतिविधियों और उपलब्धियों को समाचार के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।वैज्ञानिक अभिरुचि को बढ़ावा देने हेतु छात्रों को छोटे समूहों में वैज्ञानिक तथ्यों और प्रक्रियाओं पर चर्चा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।डॉ. शन्मुगा सुन्दरम ने स्पष्ट किया कि इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। इस पहल से न केवल छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा, बल्कि उन्हें जिम्मेदार, जागरूक और सशक्त नागरिक बनाने में भी मदद मिलेगी।

माघ मेला 2026 में आस्था और सुविधा का संगम, पर्यटन सूचना केंद्रों से श्रद्धालुओं को लाभ

लखनऊ, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेला 2026 का भव्य और दिव्य स्वरूप में शुभारंभ 3 जनवरी से हो चुका है। यह मेला न केवल धार्मिक महत्त्व रखता है, बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टि से भी प्रयागराज की नई पहचान बना रहा है। इस अवसर पर देश–विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए योगी सरकार ने व्यापक और प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं।उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए शहर के प्रमुख स्थलों पर चार अस्थायी पर्यटन सूचना केंद्र स्थापित किए हैं। 3 जनवरी से अब तक इन केंद्रों के माध्यम से करीब 20 लाख से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक लाभान्वित हो चुके हैं। इस वर्ष माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार इन केंद्रों पर श्रद्धालुओं को सही, सरल और सटीक जानकारी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।र्यटन सूचना केंद्रों पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रयागराज के प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी वाली पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही प्रशिक्षित टूरिस्ट गाइड की सूची, शहर भ्रमण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां और पंजीकृत पेइंग गेस्ट हाउस, धर्मशाला व अन्य ठहरने के विकल्प भी साझा किए जा रहे हैं। एलईडी स्क्रीन पर मेले, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता अभियान और प्रमुख पर्यटन स्थलों से जुड़े वीडियो दिखाए जा रहे हैं।

माघ मेला 2026 में श्रद्धालुओं की सुविधा को नई ऊँचाई

लखनऊ, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी विजन और मार्गदर्शन में संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेला 2026 का शुभारंभ 3 जनवरी से भव्य और दिव्य स्वरूप में हो चुका है। आस्था, सुविधा और सुव्यवस्था के संगम के रूप में विकसित हो रहा यह मेला अब केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टि से भी देश–दुनिया में नई पहचान बना रहा है। करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए योगी सरकार द्वारा व्यापक, प्रभावी और आधुनिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रयागराज के प्रमुख स्थलों पर चार अस्थायी पर्यटन सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। 3 जनवरी से अब तक इन सूचना केंद्रों के माध्यम से करीब 20 लाख से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक लाभान्वित हो चुके हैं। इस वर्ष माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज आगमन का अनुमान है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार पर्यटकों और श्रद्धालुओं को सही, सरल और सटीक जानकारी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।अस्थायी पर्यटन सूचना केंद्रों पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रयागराज के प्रमुख पर्यटन स्थलों से संबंधित विस्तृत जानकारी वाली पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही गाइड बुक, प्रशिक्षित टूरिस्ट गाइड की सूची और शहर भ्रमण से जुड़ी आवश्यक जानकारियां भी उपलब्ध हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और संतुष्टि को केंद्र में रखकर कार्य कर रही है।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए व्यापक निर्देश

लखनऊ, (संवाददाता)। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास को तेज गति से लागू कराने के उद्देश्य से ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को व्यापक दिशा–निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और सभी कार्य समयबद्ध तथा उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएँ। उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया कि योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे और कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक शुक्रवार को प्रत्येक विकास खंड की दो ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपालों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान गांव में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान "विकसित भारत–जी राम जी" अधिनियम के महत्व और इसके लाभों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को ग्राम चौपालों में पंपलेट वितरण और समूहों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'विकसित भारत–गारण्टी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' अधिनियम–2025 पारित किया गया है। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण और रोजगार गारंटी सुनिश्चित करता है। इसमें रोजगार की अवधि 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन की गई है और श्रमिकों के पारिश्रमिक भुगतान को सरल और पारदर्शी बनाया गया है।उप मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के प्रशिक्षण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी चयनित प्रशिक्षणार्थियों को पूरी क्षमता के साथ प्रशिक्षण दिया जाए। आजीविका मिशन के प्रशिक्षण एसआईआरडी में ही कराए जाएँ। प्रशिक्षणार्थियों की बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य हो और महिला सशक्तिकरण को हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विभागीय भवनों के निर्माण, बजट व्यय और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए।उप मुख्यमंत्री ने समूह सखियों की सक्रियता बढ़ाने, निष्क्रिय समूहों को सक्रिय करने और आजीविका मिशन में फील्ड में मैनपावर की समस्या शीघ्र हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदारों की बैठक बुलाने और कार्यों में देरी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को भी कहा।बैठक में राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विभाग विजयलक्ष्मी गौतम, अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग बी. एल. मीणा, महानिदेशक दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान एल. वेंकटेश्वर लू, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग सौरभ बाबू, आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग गौरी शंकर प्रियदर्शी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन निदेशक दीपा रंजन, यूपीआरआरडीए मुख्य कार्यपालक अधिकारी अंकुर कौशिक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के निदेशक इशम सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, ग्रामीण विकास कार्य अब तेज गति, उच्च गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ धरातल पर दिखाई देंगे, और महिलाओं एवं समूहों की सक्रिय भागीदारी से रोजगार और आजीविका सुनिश्चित होगी।

विनय कटियार ने अयोध्या विधानसभा से दावेदारी की इच्छा पर मची सियासी गलियारे में हलचल

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। 2027 में विधानसभा अयोध्या के चुनाव में विनय कटियार के चुनाव लड़ने की इच्छा के बाद

जिले के सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है।वही पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर चल रही वीडियो में भाजपा रामजन्म भूमि आंदोलन से जुड़े 3 बार लोक सभा (1991,1993,1999)और 2 बार राज्य सभा(2006 से 2012 और 2012 से 2018)का प्रतिनिधित्व करने वाले विनय कटियार भी विधानसभा क्षेत्र अयोध्या से लड़ने की बात कर रहे।भाजपा खाटी की उपज विनय कटियार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता अभी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विनय कटियार से उनके हिंदू धाम लखनऊ आवास पर मुलाकात भी की थी। उनके टिकट मांगने पर पार्टी पर दबाव भी रहेगा।जहां अयोध्या लोक सभा के पूर्व सांसद लल्लू सिंह विद्यार्थी परिषद की उपज है और उन्हें शुरू से ही संघ का वरदहस्त प्राप्त रहा।बताते चले कि पूर्व सांसद लल्लू सिंह शुरू से विचारधारा की राजनीति करने वाले दो बार भाजपा के जिलाध्यक्ष रहने के बाद लगातार 1991,1993, 1996,2002,2007 पांच बार के विधायक और 2014,2019 कुल दो बार के फैजाबाद अयोध्या के सांसद रहे।संगठन में 35 साल की सफल राजनीति करने वाले लल्लू सिंह जिले में अन्य दलों से आयातित विधायकों की गुटबाजी से जूझते नजर आ रहे ,वही पार्टी से जुड़े लोगों की माने तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में विरोध का कारण गुटबाजी भी रहा। लल्लू सिंह को संगठन के लोग पार्टी में बरगद की संज्ञा से नवाजते नजर आते है।लल्लू सिंह के पुत्र विकास सिंह विधानसभा के कार्यक्रमों में लगातार दिखाई पड़ रहे वही दबी जुबान चर्चा का विषय है कि लल्लू सिंह स्वयं 2027 का चुनाव लड़ने का मन बना रहे।वर्तमान भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता 2002 में साइकिल पर सवार होकर समाजवादी पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़े और 31936 मत के साथ तीसरे स्थान पर रहे इसके बाद वेद सपाई से बसपाई हुए और दल बदलकर 2012 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़कर 33481 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे।साइकिल और हाथी पर सवार होकर सफलता नहीं मिली तो भाजपा का दामन थामा और 2017 में लल्लू सिंह के सांसद होने से रिक्त हुई सीट पर हाथ आजमाने का मौका मिला और इस बार मोदी और योगी लहर में विधानसभा पहुंच गए।2022 में पुनः भाजपा से चुनाव जीतकर दुबारा विधायक बने लेकिन 2027 में उम्र 80 होने पर अपने परिवार में राजनैतिक विरासत को संजोए रखने की फिराक में है और अपने पुत्र अमल गुप्ता को विधानसभा क्षेत्र में लगातार बनाए हुए हैं। वही अंदरखाने की माने तो वेद प्रकाश गुप्ता के बड़े पुत्र विशाल गुप्ता भी 1 साल से राजनीति में सक्रिय हो गए है और वह भी अयोध्या से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते है वेद प्रकाश गुप्ता के दोनों पुत्रों के चुनाव लड़ने की इच्छा जताने के बाद लोगों की माने तो दोनों में आपस की सहमति नहीं बनने पर वेद तीसरी बार पार्टी से दावेदारी करेंगे। वेद प्रकाश गुप्ता विचारधारा बदलने सपा,बसपा और भाजपा सभी में मौका देखकर चौका मारने में माहिर खिलाड़ी है जहां भाजपा विचारधारा की राजनीति करती है वही वेद प्रकाश गुप्ता इससे इतर परिवारवाद और समय रहते मौके से दल बदल करने में माहिर है।वही विद्यार्थी परिषद की उपज और संघ के चहेते शुरू से विचारधारा की राजनीति करने वाले ऋषिकेश उपाध्याय विधानसभा अयोध्या से प्रबल दावेदार है रामजन्म भूमि आंदोलन से भी जुड़े रहे और 2017 में नगर निगम अयोध्या का भाजपा से चुनाव लड़े और नगर निगम अयोध्या के प्रथम महापौर बने।शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े और उत्कृष्ट समाजसेवी के रूप में उनकी चर्चा रहती है।अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में भाजपा के साथ रहे हैं। ऋषिकेश उपाध्याय को 2023 के नगर निगम अयोध्या के चुनाव में टिकट नहीं मिला था।संगठन द्वारा उन्हें समायोजित करने का दबाव रहेगा।वही गिरीश पति त्रिपाठी भी कांग्रेस की उपज है जिनके पिता बबुआ जी 1987 में भाजपा के अवधेश दास शास्त्री के खिलाफ अयोध्या नगर पालिका का चुनाव कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर लड़े थे और कुछ ही मतों से पराजित हुए थे। गिरीश पति त्रिपाठी का 2015 में कांग्रेस से मोहभंग हुआ और कमल पर सवार हो लिए, तीन कलश मंदिर के महंत होने और अमेठी में गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ने के कारण भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी से राजनैतिक सफर में मिलना हुआ और साल 2023 में अयोध्या नगर निगम से टिकट मिला और महापौर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पार्टी के लोगों का मानना है कि महापौर का टिकट दिलाने में स्मृति ईरानी की अहम भूमिका थी। उनके अंदर भी महापौर के बाद की अगली सीढ़ी विधानसभा का नेतृत्व करने की अलख जगी है और अंदरखाने में चर्चा है कि इस बार गिरीश पति त्रिपाठी भी विधानसभा क्षेत्र अयोध्या से चुनाव लड़ने का दम भरेंगे।वही गोसाईगंज विधानसभा से विधायक अभय सिंह के भाजपा में शामिल होने पर वहां से भाजपा का चुनाव लड़े इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू को भाजपा द्वारा कही न कही समायोजित करने का दबाव रहेगा, और खब्बू अयोध्या से दावेदारी भी कर सकते हैं भाजपा से जुड़े वरिष्ठ लोगों का यह भी मानना है कि वेद प्रकाश गुप्ता की उम्र के तगाजे को देखते हुए खब्बू को पार्टी अयोध्या विधानसभा में समायोजित कर सकती है। तो वहीं जन चर्चा और पार्टी के सूत्रों की माने तो अयोध्या विधानसभा से दावेदारी में भाजपा नेता शक्ति सिंह, अभिषेक मिश्रा भी प्रमुख है।

संक्षिप्त खबरें

राम मंदिर परिसर मे युवती समेत तीन लोगों ने घुसकर नमाज पढ़ने की कोशिश, गिरफ्तार

अयोध्या।अभी तीन दिन पहले प्रयागराज में होने वाले माघ मेले को लेकर यहां पर श्रद्धालुओं के आने वाली भारी संख्या मे भीड़ का अंदेशा देखते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की बात कही थी।क्योंकि देखा जाये तो राम मंदिर निर्माण के बाद से मथुरा, काशी, प्रयागराज की भी भीड़ रामनगरी मे रामलला का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भी रहती है।जिसको लेकर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने राम मंदिर सुरक्षा को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की बात कही थी।लेकिन राम जन्मभूमि मंदिर परिसर की सुरक्षा घेरा मे उस समय सेंध लगा जब शनिवार को भोर 3:00 बजे सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर एक युवती समेत तीन लोग डी 1 गेट से राम मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए और नमाज पढ़ने की कोशिश किया इससे पहले वह नमाज पढ़ने कि वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें ऐसा करणी से रोक कर उन्हें हिरासत में ले लिया।पकड़े गए लोगों में दो युवक तथा एक युवती बताई जा रहे हैं।बताया जा रहा है कि तीनो लोग सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने के लिए युवक बैठ गये।पुलिसवालों ने उसे उसे ऐसा करते देखते ही हिरासत में ले लिया।हिरासत मे लिए गए एक युवक कश्मीरी वेशभूषा में थे।इसमे पकड़े गए एक युवक की पहचान अबू अहमद शेख निवासी कश्मीर के शोपियां निवासी के रुप मे हुई है।वहीं पकड़ी गई युवती का नाम सोफिया बताया जा रहा है।जबकि एक अन्य युवक का नाम अभी पता नहीं चल पाया है।मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सुरक्षाकर्मियों ने जब युवकों को रोका, तो उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी।वहीं इस संबंध मे घटना की सूचना मिलते ही खुफिया एजेंसियां,स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी सक्रिय हो गए हैं।हालांकि, इस मामले पर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।वही राम मंदिर ट्रस्ट ने भी पूरे प्रकरण पर चुप्पी साध रखी है।

यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले 162 वाहन चालकों पर हुई कार्यवाई

अयोध्या। शनिवार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत एआरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर आरपी सिंह एवं यात्री कर अधिकारी ने संयुक्त रूप से यातायात नियमों की एंडोखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही किया। इस मौके पर इन दोनों अधिकारियों ने हेलमेट, सीटबेल्ट

का प्रयोग करते न पाए जाने तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करते पाए जाने एवं विपरीत दिशा में वाहन का संचालन करने पर 162 चालान किए। ए आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर आरपी सिंह ने बताया कि यह अभियान विभिन्न मार्गो तथा चौराहों पर आगे भी चलता रहेगा। बताया कि जहां ओर यातायात नियमों के प्रति वाहन चालकों सहित अन्य लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम चलाया जाएगा वही यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों और स्वामियों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा।

आईजी आरएस मासिक रैंकिंग में रेंज व सभी पांच जिलों को मिला प्रथम स्थान

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व में पुलिस विभाग की सुदृढ़ व्यवस्था और प्रभावी कार्यप्रणाली से दिव्य और भव्य अयोध्या में एक बार फिर सुशासन, सुरक्षा और मर्यादा का वातावरण स्थापित होता दिखाई दे रहा है। वहीं प्रदेश पुलिस की जन शिकायत निस्तारण प्रणाली(आईजीआरएस) में एक बार फिर अयोध्या परिक्षेत्र ने शानदार प्रदर्शन किया हैं। एडीजीध्आईजी अयोध्या प्रवीण कुमार के कुशल निर्देशन और आईजीआरएस टीम की अथक मेहनत से परिक्षेत्र को मासिक रैंकिंग में पुनः प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे खास बात यह है कि परिक्षेत्र के सभी पांच जिलों अयोध्या, अम्बेडकरनगर, अमेठी, बाराबंकी और सुल्तानपुर को भी अलग–अलग प्रथम रैंक मिली है। यह उपलब्धि पुलिस की जनता के प्रति संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति और जन शिकायतों के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर देने के कारण प्रदेश भर में आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों का तेजी से समाधान हो रहा है। अयोध्या परिक्षेत्र में यह सफलता लगातार टीम वर्क और अधिकारियों की सक्रियता का नतीजा हैं।शिकायतकर्ताओं से संतुष्टि फीडबैक लेने और डिफॉल्ट मामलों को न्यूनतम रखने में टीम ने उत्कृष्ट कार्य किया। एडीजीध्आईजी प्रवीण कुमार ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि यह सफलता हमारी आईजीआरएस टीम की मेहनत और सभी जिलों के पुलिस कप्तानों व थाना प्रभारियों की समर्पण भावना का परिणाम है। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है कि जनता की हर शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो। हमारा प्रयास रहेगा कि अयोध्या परिक्षेत्र हर महीने इसी तरह अव्वल रहे और जनता का विश्वास पुलिस पर और मजबूत हो।इस रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने से परिक्षेत्र के पुलिसकर्मियों का मनोबल ऊंचा हुआ है। जिलों में थानों पर शिकायतों का त्वरित समाधान, फॉलो–अप और शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने की प्रक्रिया को और मजबूत किया गया है। रामनगरी अयोध्या सहित पूरे परिक्षेत्र में पर्यटन और धार्मिक आयोजनों के कारण शिकायतों की संख्या अधिक रहती है, फिर भी टीम ने इसे चुनौती बनाकर सफलता हासिल की। यह उपलब्धि अन्य परिक्षेत्रों के लिए भी प्रेरणादायक है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनसेवा और पारदर्शिता ही उनकी प्राथमिकता है। आने वाले महीनों में भी इसी प्रदर्शन को बनाए रखने का संकल्प लिया गया है।

कम्युनिकेशन, निगोशिएशन और सॉफ्ट स्किल्स से मिलती है कॉर्पोरेट में सफलता - प्रो. आशीष सिंह

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर ,वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा षबिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर मैनेजेरियल इफेक्टिवनेसष विषय पर आयोजित विशेष व्याख्यानमाला का शनिवार को आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रबंधन संकाय, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, मीरजापुर से प्रो. आशीष सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विभागाध्यक्ष डॉ. रसिकेश द्वारा मुख्य वक्ता के औपचारिक परिचय से हुई। व्याख्यान में मुख्य वक्ता प्रो. आशीष सिंह ने प्रभावी संप्रेषण, निर्णय–निर्माण, नेतृत्व तथा समस्या–समाधान कौशल के महत्व को व्यावहारिक उदाहरणों से स्पष्ट करते हुए विस्तार से प्रकाश डाला । उन्होंने कहा कि स्पष्ट, उद्देश्यपूर्ण और नैतिक संप्रेषण से संगठनात्मक कार्यकुशलता बढ़ती है तथा प्रबंधकीय विश्वसनीयता मजबूत होती है। कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी छात्रों की जिज्ञासाओं का भी उन्होंने उदाहरणों सहित समाधान दिया। विभाग के वरिष्ठ आचार्य प्रो. अविनाश पाथर्डीकर ने मुख्य वक्ता का स्वागत किया और संप्रेषण कौशल के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य के प्रबंधकों के लिए एआई–सक्षम संप्रेषण और डिजिटल दक्षता अनिवार्य हैं। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉ. रसिकेश ने किया। इस अवसर पर विभाग के शिक्षक अनुपम कुमार, दीपक सैनी, शची सिंह, दिव्यांशु सिंह, अनुराग गुप्ता, पीयूष सिंह, जान्हवी राय, साधना मौर्य, राज सैनी सहित विभिन्न शोध छात्र–छात्राएं उपस्थित रहीं।

योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, शिकायत पर होगी सख्त कार्रवाई : ए.के. शर्मा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि योजनाओं की प्रगति अथवा क्रियान्वयन में अनियमितता अथवा लापरवाही की शिकायत प्राप्त होती है, तो उसकी जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह चेतावनी उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के मंत्री तथा जनपद के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा ने शनिवार को अधिकारियों को दी। प्रभारी मंत्री पुलिस लाइन जौनपुर में आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में शासन स्तर से संचालित समस्त विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का शत–प्रतिशत लाभ सुनिश्चित कराया जाए। ए.के. शर्मा ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार की योजनाएं आमजन के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही हैं। ऐसे में इनके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को योजनाओं की नियमित समीक्षा करते हुए कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। शीतलहर को देखते हुए प्रभारी मंत्री ने जनपद के रैन बसेरों की व्यवस्थाओं की भी विशेष समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी रैन बसेरों में साफ–सफाई, पर्याप्त कंबल, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, शौचालय सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए, इसके लिए नगर निकायों, पुलिस तथा संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर निरंतर अभियान चलाया जाए। साथ ही ठंड के दृष्टिगत विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त संख्या में अलाव जलाने के भी निर्देश दिए गए।

संक्षिप्त खबरें

समीक्षा बैठक में अयोध्या विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने चल रहे कार्य को शीघ्र करने के लिए निर्देश

(राजन तिवारी संवाददाता अयोध्या धाम)

अयोध्या।शनिवार को उपाध्यक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण अनुराज जैन द्वारा प्राधिकरण सभागार में प्राधिकरण द्वारा कराये जा रहे परियोजनाओं के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की गयी।उक्त बैठक में प्राधिकरण के सचिव, विशेष कार्याधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, वित्त एवं लेखाधिकारी, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता, राइट्स लिमिटेड, कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। अयोध्या शहर में विभिन्न स्थानों पर वर्षा ऋतु में जल भराव की समस्या रहती है जिसके निस्तारण हेतु प्राधिकरण द्वारा 05 नालो के निर्माण का कार्य किया जा रहा है।इस मौके पर नालों की समीक्षा की गयी।फतेहगंज सब्जी मण्डी से निकलकर चौदहकोसी परिकमा मार्ग पर पठान टोला तक जाने वाले नाले के निर्माण हेतु फतेहगंज सब्जीमण्डी से साहबगंज तक कच्चे नाले का विकास कार्य–प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण का कार्य शामिल रहे।उपाध्यक्ष ने उक्त नालों की कार्यदायी संस्था एक्मे को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि स्थल पर कार्य बहुत ही धीमी गति से किया जा रहा है और प्रगति संतोषजनक नहीं है।मैनपावर बढ़कार निर्माण कार्य को त्वरित गति से गुणवत्तापूर्वक करते हुए 31 मार्च, 2026 तक निर्माण कार्य प्रत्येक दशा में पूर्ण करायें।यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होता है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह से कौशलपुरी फेज–1 एवं फेज–2, अवध विहार, ट्रांसपोर्ट नगर नाले के विकास का कार्य, जालपा नाले का विकास कार्य एवं तेलाई नाले का विकास कार्य कर रहे कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिये गये कि निर्माण कार्य में प्रगति लाते हुए निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्वक कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। प्राधिकरण द्वारा विकसित अयोध्या शहर में कौशलपुरी आवासीय योजना फेज–1 एवं फेज–2 में स्थित विभिन्न सामुदायिक पार्को तथा साकेतपुरी आवासीय योजना भाग–1 एवं भाग – 2 में स्थित विभिन्न सामुदायिक पार्को के सौन्दर्गीकरण का कार्य, तहसील सोहावल में स्थित सुरवारी झील के संरक्षण एवं जीर्णोद्वार का कार्य, अयोध्या शहर में स्थित 15 सड़कों एवं नालियों के निर्माण कार्य, फैजाबाद चौक क्षेत्र में स्थित मच्छरहट्टा पार्किंग का निर्माण कार्य, अयोध्या में स्थित पारम्परिक शवदाह स्थल पर जनसुविधाओं के विकास कार्य, अयोध्या में रामपथ के दोनो ओर अवशेष रिक्त भूमि के सैन्दर्गीकरण एवं विकास कार्य, अयोध्या में सरयू नदी में फ्ल्होटिंग पब्लिक बाथिंग कुण्ड का निर्माण कार्य, अयोध्या विकास प्राधिकरण एवं अयोध्या नगर निगम कार्यालय भवन का निर्माण कार्य, राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत जनपद अयोध्या के नगर निगम अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत नजूल भूमि पर यात्री निवास का निर्माण कार्य तथा प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही वशिष्ठ कुंज योजना फिरोजपुर उपरहार आवासीय योजना के विकास कार्यो की विस्तृत रूप से समीक्षा बैठक की गयी। उपाध्यक्ष द्वारा समीक्षा बैठक में कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि सभी कार्यदायी संस्थायें कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओ को निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। यदि कार्यदायी संस्था निर्धारित समय में परियोजना को पूर्ण नहीं कर पाती हैं तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

एक करोड़ से अधिक की 150 लोगो से आनलाइन ठगी का आरोपीत प्रियम श्रीवास्तव गिरफ्तार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर पुलिस ने एक करोड़ से अधिक और 150 लोगो से आनलाइन ठगी करने वाले एक शातिर अपराधी को शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।मामले का शनिवार को खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक शहर आयुष श्रीवास्तव ने बाताया कि जलालपुर थाना क्षेत्र के कबूलपुर गाँव निवासी प्रियम श्रीवास्तव पुत्र राजकुमार श्रीवास्तव ने फर्जी तरीके से राजरीता फर्म बनाकर ए 4 साइज के पेपर व नोटबुक बनाकर डिलेवरी करने का झांसा देकर लोगो से आर्डर लेता था और उसका पैसा आनलाइन पैसा अपने परिवार के लोगों के नाम से बनाये गये फर्जी ढंग से एकाउंट में मंगवाता था.जिस एकाउंट की जानकारी सम्बन्धित घर वालो को भी नही होती थी। जब ग्राहक डिलेवरी के लिए बिल मांगते थे तो ये इनवाईस मेकर एप के दवारा अपने फर्म राजरीता का फर्जी बिल बनाता था और पिक्स आर्ट एप के दवारा आनलाइन डीटीडीसी कोरियर का फर्जी बिल्टी बनाकर उनके व्हात्सएप नम्बर पर भेज देता था लेकिन माल डिलेवर नही करता था। साथ ही एक्स पोर्टर इण्डिया और इण्डिया मार्ट जैसे प्लेटफार्म का उपयोग करके आनलाईन बेबसाईट के मध्यम से ग्राहक खोजता था और गेमिंग प्लेटफार्म पर पैसे मंगा लेता था। बैंक खाते कि जाँच पड़ताल करने पर इसके खाते में 2021 से अबतक 1 करोड़ से अधिक फर्जी ट्रांजेक्शन किया गया है। इसके उपर अबतक विभिन्न राज्यों में कुल 21एनसीआरपी कम्प्लेंन होना पाया गया है। और पुलिस पूछताछ में ये भी सामने आया कि ये नेपाल और फिलिपिन्स जैसे विदेशो में भी आनलाईन ठगी कर चूका है। जल्द रूपये कमाने और बड़ा आदमी बनने के चक्कर में यह गेमिंग एप भी चलाता था इसके पास से पुलिस ने चार मोबाईल फोन भी जब्त किया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब नगर कोतवाली में नगर के परमानतपुर मोहल्ला निवासी अखंड प्रताप सिंह ने इसके खिलाफ थाने में तहरीर दिया और आरोप लगाया कि प्रियम श्रीवास्तव ने फर्जी तरीके से उससे ए4 साइज पेपर देने के नाम पर ढाई लाख रूपये अपने एकाउंट में मंगवा लिया है। लगभग मुझे 4 साल लगातार दौड़ा रहे है और न ही माल दे रहे है और न ही पैसा दे रहे है। इस पर साइबर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए प्रतिबिम्ब पोर्टल से प्राप्त संदिग्ध को गिरफ्तार किया।जिससे पुरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने पूछताछ में प्रियम श्रीवास्तव ने बताया कि आनलाईन ठगी कर जो पैसा जमा किया है। उससे उसने अपनी खुद की शादी की और गाँव में एक अच्छा सा मकान बनाया और एक चार पहिया गाडी खरीदी। जिससे वो चलता था हालंकि बड़ा आदमी बनने के चक्कर में खुद को इस अपराध की दुनिया में ले आया। आरोपित प्रियम श्रीवास्तव ने इंटर तक की पढाई करने के बाद खुद को व्यापार में उतार लिया और इसने सबसे पहले ब्रेड की सप्लाई का काम शुरू किया। उसके बाद से 2017 में खुद रीता राज नाम की एक फर्म डाली और उसी कारोबार शुरू किया। उस फर्म ने वो नोटबुक ए4 पेपर बनाया जाता था। हालंकि उनकी मा आशा कार्यकर्ती और परिवार में पिता कुछ नही करते है।

जिला गंगा समिति, जिला पर्यावरण समिति एवं जिला वृक्षारोपण समिति की संयुक्त बैठक सम्पन्न

(राजन तिवारी संवाददाता अयोध्या धाम)

अयोध्या।डीएम निखिल टीकाराम फुंडे के निर्देश पर जिला गंगा समिति, जिला पर्यावरण समिति एवं जिला वृक्षारोपण समिति की संयुक्त बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सीडीओ कृष्ण कुमार सिंह की अध्यक्षता व डीएफओ प्रखर गुप्ता की सह अध्यक्षता में संपन्न हुई।बैठक में गंगा स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।बैठक मे सीडीओ ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत संचालित गतिविधियों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि गंगा एवं उसकी सहायक नदियों को स्वच्छ एवं अविरल बनाए रखने हेतु ठोस कार्ययोजना के साथ प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने कहा कि जन सहभागिता के माध्यम से स्वच्छता अभियान को और अधिक सशक्त बनाया जाए। नदियों के किनारे अतिक्रमण होने से रोका जाए। साथ ही नालों की नियमित साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाए।जिला पर्यावरण समिति की समीक्षा करते हुए वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छता से जुड़े अभियानों पर विशेष जोर दिया गया।सीडीओ ने निर्देश दिए कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सभी योजनाओं में आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि गीले और सूखे कूड़े का निस्तारण उचित तरीके से कराया जाए। सीमा राय अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गोसाईगंज द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि निकाय का गीला कूड़ा व सब्जीध्फल आदि के छिलके को रोटी बैंक में दिया जाता है, जो गौशालाओ को दिया जाता है। जिस पर सीडीओ ने कहा कि अन्य निकायों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इस प्रकार गीले कूड़े को इकट्ठा कर गौशाला में दे जिससे उसका सही उपयोग हो सकें।इसी प्रकार संजय कुमार अधिशासी अधिकारी कुमारगंज ने बताया कि सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा डोर टू डोर कलेक्ट किया जाता है और सूखे और गले कूड़े को संचालित एमआरएफ सेंटर में ले जाकर उसका निस्तारण किया जाता है ।जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक में आगामी वृक्षारोपण अभियानों की तैयारी, लक्ष्य निर्धारण एवं पौधों की देखरेख पर चर्चा की गई। सीडीओ ने कहा कि वृक्षारोपण केवल लक्ष्य पूर्ति तक सीमित न रहे, बल्कि पौधों के संरक्षण एवं जीवित रहने की दर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।बैठक में गुरु प्रसाद पाण्डेय सहायक नगर आयुक्त नगर निगम, आर. के. गौतम अधिशासी अभियंता सिंचाई, अश्वनी कुमार ए. ई. जल निगम ग्रामीण, सुषमा देवी मत्स्य अधिकारी, श्वेता साहू जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे व संबंधित विभागों के अधिकारी जिला गंगा समिति सदस्य अशोक कुमार मिश्रा, एस. बी. सिंह सहित अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।